

DAILY CURRENT AFFAIRS

IN HINDI

SPECIAL FOR UPSC & GPSC EXAMINATION

DATE : 25-12-25



The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Thursday, 25 Dec, 2025

Edition : International Table of Contents

Page 01 Syllabus : GS 3 : Science and Technology/ Prelims	इसरो के LVM3 रॉकेट ने सबसे बड़ा कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया
Page 06 Syllabus : GS 1 : Indian Society	जाट पंचायत ने शादीशुदा महिलाओं के स्मार्टफोन इस्तेमाल पर रोक लगाई
Page 08 Syllabus : GS 3 : Environment / Prelims	मैग्नेटिक मोमेंट भारत को अपने क्लीन एनर्जी ट्रांज़िशन में ग्रीन कंप्लायंस को कमज़ोर नहीं करना चाहिए
Page 10 Syllabus : GS 3 : Indian Economy / Prelims	भारत में मैनुफैक्चरिंग क्यों पिछड़ गई है?
Page 10 Syllabus : GS 2 : Governance	ब्यूरो ऑफ़ पोर्ट सिक्योरिटी क्या है और इसकी भूमिका क्या है?
Page 08 : Editorial Analysis Syllabus : GS 2 : Governance	नए लेबर कोड, अनौपचारिक मज़दूरों के लिए खतरे

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने हेवी-लिफ्ट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 (एलवीएम 3) का उपयोग करके ब्लूबर्ड ब्लॉक -2 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इस मिशन ने अमेरिकी ग्राहक के लिए भारत के पहले समर्पित वाणिज्यिक एलईओ लॉन्च को चिह्नित किया और वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत के बढ़ते कद को मजबूत करते हुए अब तक के सबसे बड़े वाणिज्यिक संचार उपग्रह को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया।

ISRO's LVM3 rocket launches largest commercial communications satellite

Hemanth C.S.
BENGALURU

The Indian Space Research Organisation (ISRO) placed the BlueBird Block-2 satellite in a low earth orbit (LEO) on Wednesday.

The Launch Vehicle Mark 3 (LVM3) lifted off from the second launch pad of the Satish Dhawan Space Centre in Sriharikota at 8.55 a.m., and 15 minutes later, placed the satellite in the intended orbit.

The ISRO accomplished two milestones with this mission as it was able to deploy the largest commercial communications satellite in a low earth orbit, and the BlueBird Block-2 satellite, weighing 6,100 kg, became the heaviest

payload to be launched by LVM3 from Indian soil.

"LVM3 Bahubali rocket M6 launch vehicle has successfully and precisely injected the BlueBird Block-2 communication satellite in the intended orbit. This is the first dedicated commercial launch for a customer from the U.S.," ISRO Chairman V. Narayanan said. The BlueBird Block-2 communication satellite, developed by AST Space-Mobile in the U.S., is part of a next generation of the communication satellites, designed to provide space-based cellular broadband connectivity directly to standard mobile smartphones.

"I am extremely happy to announce the performance of the orbit that we

have got is less than two kilometres. This is one of the best performances of any launch vehicle in the global arena," Dr. Narayanan said.

Display of reliability

Wednesday's success demonstrated the reliability of India's space programme, Prime Minister Narendra Modi said. "Powered by India's youth, our space programme is getting more advanced and impactful. With LVM3 demonstrating reliable heavy-lift performance, we are strengthening the foundations for future missions such as Gaganyaan, expanding commercial launch services and deepening global partnerships. This increased capability and boost to

self-reliance are wonderful for the coming generations," Mr. Modi posted on X.

"BlueBird block-2 mission is part of a global LEO constellation to provide direct-to-mobile connectivity through satellite. This constellation will enable 4G and 5G voice and video calls, texts, streaming, and data for everyone, everywhere, at all times. It features a 223m² phased array, making it the largest commercial communications satellite ever deployed into low Earth orbit," the ISRO said.

Dr. Narayanan said that the LVM3-M6 mission was the 104th launch from Sriharikota and also the ninth successful mission of the LVM3 launch vehicle.



New horizons: ISRO's LVM3 lifts off carrying the Bluebird Block-2 satellite from Sriharikota on Wednesday. AFP

मिशन के मुख्य तथ्य

- पेलोड: ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 उपग्रह (6,100 किग्रा), एसटी स्पेसमोबाइल द्वारा विकसित
- कक्षा: लो अर्थ ऑर्बिट (LEO)
- प्रक्षेपण यान: LVM3 (बाहुबली) – मिशन LVM3-M6

विशेष उपलब्धियां:

- LEO में तैनात सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार उपग्रह
- LVM3 द्वारा भारतीय धरती से लॉन्च किया गया सबसे भारी पेलोड
- श्रीहरिकोटा से 104वां प्रक्षेपण; 9वां सफल LVM3 मिशन
- उपग्रह क्षमता: डायरेक्ट-टू-मोबाइल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी (4जी/5जी, आवाज, वीडियो, डेटा)

यह लॉन्च क्यों मायने रखता है

1. तकनीकी महत्व

- सटीक कक्षीय इंजेक्शन (त्रुटि < 2 किमी) प्रदर्शित करता है, LVM3 को विश्व स्तर पर विश्वसनीय हेवी-लिफ्ट लॉन्च वाहनों में रखता है।
- पारंपरिक सरकारी मिशनों से परे, बहुत बड़े, जटिल वाणिज्यिक पेलोड को संभालने में इसरो की क्षमता की पुष्टि करता है।

- अगली पीढ़ी के उपग्रह आर्किटेक्चर जैसे चरणबद्ध सरणी, डायरेक्ट-टू-डिवाइस सिस्टम के लिए भारत की तत्परता को मान्य करता है।

2. वाणिज्यिक स्थान और न्यूस्पेस पारिस्थितिकी तंत्र

- यह उच्च मूल्य वाली वाणिज्यिक LEO लॉन्च सेवाओं में भारत के प्रवेश को चिह्नित करता है, जो पारंपरिक रूप से अमेरिका और यूरोप का प्रभुत्व है।
- LEO नक्षत्रों की बढ़ती वैश्विक मांग के बीच एक लागत प्रभावी, विश्वसनीय प्रक्षेपण प्रदाता के रूप में इसरो के आकर्षण को बढ़ाता है।
- इन-स्पेस और एनएसआईएल ढांचे के तहत निजी कंपनियों को पूरक बनाकर भारत की न्यूस्पेस नीति के उद्देश्यों का समर्थन करता है

3. रणनीतिक और भू-राजनीतिक आयाम

- उन्नत अंतरिक्ष अनुप्रयोगों में भारत-अमेरिका तकनीकी सहयोग को मजबूत करता है।
- वैश्विक अंतरिक्ष मूल्य श्रृंखला, विशेष रूप से उपग्रह ब्रॉडबैंड में भारत की उपस्थिति का विस्तार करता है - एक ऐसा क्षेत्र जिसमें नागरिक, वाणिज्यिक और रणनीतिक प्रासंगिकता है।
- स्वदेशी हेवी-लिफ्ट और मिशन विश्वसनीयता का प्रदर्शन करके भारत की सॉफ्ट पावर में सुधार करता है।

4. भविष्य के भारतीय मिशनों के लिए निहितार्थ

- गगनयान जैसे मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशनों के लिए परिचालन विश्वास, जो एलवीएम 3 पर भी निर्भर करता है।
- भविष्य के गहरे अंतरिक्ष, अंतरिक्ष-स्टेशन समर्थन और भारी पेलोड क्षमता की आवश्यकता वाले अंतरग्रहीय मिशनों के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है।

5. विकासात्मक और शासन प्रासंगिकता

- LEO-आधारित डायरेक्ट-टू-मोबाइल कनेक्टिविटी डिजिटल डिवाइड को पाटने में मदद कर सकती है, खासकर दूरदराज और आपदा-प्रवण क्षेत्रों में।
- वैश्विक बाजार प्रासंगिकता के साथ उच्च अंतः स्वदेशी तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन करके डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के साथ तालमेल बिठाता है।

राजनीतिक और नीतिगत महत्व

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मिशन आत्मनिर्भरता को मजबूत करता है, वाणिज्यिक लॉन्च सेवाओं को बढ़ावा देता है और वैश्विक साझेदारी को गहरा करता है। यह अंतरिक्ष को एक रणनीतिक आर्थिक क्षेत्र के रूप में मानने के लिए भारत की व्यापक नीति के अनुरूप है, न कि केवल एक वैज्ञानिक प्रयास के रूप में।

चुनौतियाँ और आगे का रास्ता

- पुनः प्रयोज्य लॉन्च सिस्टम से बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बीच लॉन्च ताल को बनाए रखना।
- सुरक्षा से समझौता किए बिना तेजी से व्यावसायीकरण का समर्थन करने के लिए नियामक चपलता सुनिश्चित करना।
- निजी भारतीय प्रक्षेपण और उपग्रह फर्मों को बड़ी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एकीकृत करना।

निष्कर्ष

ब्लूबर्ड ब्लॉक-3 का सफल LVM2 लॉन्च एक तकनीकी उपलब्धि से कहीं अधिक है; यह एक सक्षम अंतरिक्ष यात्रा करने वाले देश से एक प्रतिस्पर्धी वैश्विक अंतरिक्ष सेवा प्रदाता के रूप में भारत के परिवर्तन का संकेत देता है। तकनीकी विश्वसनीयता, वाणिज्यिक विश्वसनीयता और रणनीतिक दूरदर्शिता के संयोजन से, इसरो ने विकसित हो रही एलईओ-संचालित अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति को मजबूत किया है। यूपीएससी के परिप्रेक्ष्य में, यह आयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और शासन के प्रतिच्छेदन का उदाहरण है, जो इसे एक उच्च मूल्य वाला करंट अफेयर्स विकास बनाता है।

UPSC प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन भारत के लिए LVM3 के रणनीतिक महत्व को सबसे अच्छी तरह से समझाता है?

- (a) यह मुख्य रूप से छोटे उपग्रह प्रक्षेपणों के लिए डिज़ाइन किया गया है
- (b) यह पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण क्षमता को सक्षम बनाता है
- (c) यह मानव अंतरिक्ष उड़ान सहित भारी पेलोड मिशनों का समर्थन करता है
- (d) यह ध्रुवीय मिशनों के लिए पीएसएलवी का स्थान लेता है

उत्तर: c)

यूपीएससी मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

प्रश्न: लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) उपग्रह नक्षत्र वैश्विक संचार बुनियादी ढांचे को नया आकार दे रहे हैं। LEO उपग्रहों के लाभों पर चर्चा करें और देखें कि भारत का LVM3 इस क्षेत्र में अपनी भूमिका को कैसे मजबूत करता है। (150 शब्द)

राजस्थान के जालोर जिले में जाट समुदाय से संबंधित एक जाति पंचायत ने 26 जनवरी, 2026 से 15 गांवों में विवाहित महिलाओं और युवा महिलाओं द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का फरमान जारी किया है। जबकि इस निर्णय को मोबाइल की लत और बच्चों के नेत्र स्वास्थ्य जैसे आधारों पर उचित ठहराया गया है, इसने पितृसत्तात्मक नियंत्रण को मजबूत करने, संवैधानिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने और डिजिटल लिंग विभाजन को गहरा करने के लिए व्यापक आलोचना शुरू कर दी है। यह प्रकरण समकालीन भारत में पारंपरिक सामाजिक संस्थानों और संवैधानिक नैतिकता के बीच जारी तनाव पर प्रकाश डालता है।

पृष्ठभूमि और संदर्भ

- यह निर्णय गाजीपुर गांव में चौधरी वंश की सुंधामाता पट्टी जाति पंचायत ने लिया है।
- विवाहित महिलाओं और बहुओं को शादियों, सार्वजनिक समारोहों या यहां तक कि पड़ोस की यात्राओं में कैमरा-सक्षम स्मार्टफोन ले जाने से प्रतिबंधित किया गया है।
- वॉयस कॉल के लिए केवल बुनियादी कीपैड फोन की अनुमति है।
- शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों को शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए घर पर स्मार्टफोन के सीमित उपयोग की अनुमति है।
- प्रस्ताव का कोई वैधानिक समर्थन नहीं है, लेकिन यह सामाजिक दबाव और सामुदायिक प्रवर्तन पर निर्भर करता है।
- इस तरह की जाति पंचायतों (जिन्हें अक्सर गैर-संवैधानिक निकायों के रूप में जाना जाता है) ने ऐतिहासिक रूप से विवाह, गतिशीलता, ड्रेस कोड और व्यवहार से संबंधित सामाजिक आदेश जारी किए हैं, विशेष रूप से महिलाओं को लक्षित करते हैं।

शामिल प्रमुख मुद्दे

1. संवैधानिक और कानूनी चिंताएँ

- मौलिक अधिकारों का उल्लंघन:
 - अनुच्छेद 14: लिंग और वैवाहिक स्थिति के आधार पर भेदभावपूर्ण व्यवहार।

Jat panchayat bans smartphone use by married women

The Hindu Bureau
JAIPUR

When the world is racing on the highway of connectivity, smartphones will be prohibited for married women belonging to a sect of the Jat community in Rajasthan's Jalore district from Republic Day in 2026. The diktat was issued at a caste panchayat held in Ghazi-pur village on December 21.

The panchayat ordered that no daughter-in-law or young woman from 15 villages in the Bhinmal-Khanpur area carry camera-enabled mobile phones to weddings, public gatherings, and even while visiting neighbours, from January 26. They can use only basic keypad phones for voice calls.

The Sundhamata Patti panchayat of the Chaudhary clan took the decision "with consensus", citing

concerns of mobile addiction and the impact of screentime on children's eyesight. Panch Himmataram read out the proposal, which was passed as a resolution after discussions among all panchayat members and elders, who agreed to implement the rule.

Community head Sujanaram Chaudhary presided over the panchayat meeting. The resolution stated that girls pursuing education would be allowed to use smartphones at home "strictly for academic purposes", but would be barred from carrying the devices to social events, weddings or neighbourhood visits.

A video footage of the proclamation being read out at the panchayat meeting was circulated online, drawing sharp criticism from social activists and women's rights groups.

- अनुच्छेद 19(1)(a): अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना तक पहुंच पर प्रतिबंध।
- अनुच्छेद 21: व्यक्तिगत स्वतंत्रता, गरिमा और स्वायत्तता का उल्लंघन (जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विस्तार से व्याख्या की गई है)।
- कानूनी अधिकार का अभाव: जाति पंचायतों की कोई संवैधानिक या वैधानिक वैधता नहीं है। उनके प्रस्ताव कानून में लागू करने योग्य नहीं हैं, लेकिन अक्सर सामाजिक दबाव, बहिष्कार या अनौपचारिक प्रतिबंधों के माध्यम से संचालित होते हैं।

2. लैंगिक न्याय और पितृसत्ता

- यह प्रतिबंध गहराई से जड़ें जमाए हुए पितृसत्तात्मक मानदंडों को दर्शाता है, जहां सामाजिक व्यवस्था और नैतिकता के नाम पर महिलाओं की गतिशीलता, संचार और दृश्यता को नियंत्रित किया जाता है।
- महिलाओं पर चयनात्मक प्रतिबंध, जबकि पुरुषों के स्मार्टफोन का उपयोग अनियमित रहता है, "सम्मान", निगरानी और आज्ञाकारिता की लैंगिक रूढ़िवादिता को मजबूत करता है।
- इस तरह के उपाय महिला-केंद्रित नीतियों, कानूनी सुधारों और न्यायिक सक्रियता के माध्यम से दशकों की प्रगति को कमजोर करते हैं।

3. डिजिटल लिंग विभाजन

- भारत पहले से ही डिजिटल पहुंच में एक महत्वपूर्ण लैंगिक अंतर का सामना कर रहा है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में।
- स्मार्टफोन आज केवल संचार उपकरण नहीं हैं, बल्कि इसके प्रवेश द्वार हैं:
 - शिक्षा और ऑनलाइन सीखना
 - वित्तीय समावेशन (यूपीआई, डीबीटी, बैंकिंग ऐप्स)
 - स्वास्थ्य सेवाएं (टेलीमेडिसिन, जागरूकता)
 - सरकारी योजनाएं और शिकायत निवारण
- स्मार्टफोन तक महिलाओं की पहुंच को प्रतिबंधित करने से उन्हें डिजिटल अर्थव्यवस्था और शासन पारिस्थितिकी तंत्र से हाशिए पर रखने का जोखिम है।

4. सामाजिक तर्क बनाम अधिकार-आधारित दृष्टिकोण

घोषित औचित्य:

- मोबाइल की लत
- बच्चों की आंखों का स्वास्थ्य
- सामाजिक अनुशासन

महत्वपूर्ण मूल्यांकन:

- ये चिंताएं लिंग-विशिष्ट नहीं हैं और इन्हें व्यापक प्रतिबंध के बजाय जागरूकता, डिजिटल साक्षरता और माता-पिता के मार्गदर्शन के माध्यम से संबोधित किया जा सकता है।
- महिलाओं को अलग करना इंगित करता है कि अंतर्निहित मुद्दा सामाजिक नियंत्रण है, सार्वजनिक स्वास्थ्य नहीं।

5. शासन और कानून के शासन के लिए निहितार्थ

- इस तरह के आदेश शासन के समानांतर मानदंडों का निर्माण करके संवैधानिक राज्य के अधिकार को चुनौती देते हैं।
- निर्णायक रूप से प्रतिक्रिया देने में विफलता कहीं और इसी तरह के अतिरिक्त-कानूनी सामाजिक आदेशों को प्रोत्साहित कर सकती है।
- यह प्रकरण अधिकारों के उल्लंघन को रोकने में जिला प्रशासन, पुलिस और राज्य महिला आयोगों की भूमिका के बारे में सवाल उठाता है।

आगे की राह

प्रशासनिक कार्रवाई:

- जिला अधिकारियों को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करना चाहिए कि इस तरह के प्रस्तावों की कोई कानूनी वैधता नहीं है।
- आदेश से उत्पन्न होने वाले जबरदस्ती, धमकी या सामाजिक बहिष्कार को रोकें।

कानूनी सुरक्षा उपाय:

- महिलाओं की स्वायत्तता और गरिमा की रक्षा करने वाले कानूनों के कार्यान्वयन को मजबूत करना।
- यदि आवश्यक हो तो गैरकानूनी सभाओं और जबरदस्ती सामाजिक प्रथाओं के खिलाफ मौजूदा कानूनी प्रावधानों का उपयोग करें।

सामाजिक और डिजिटल जागरूकता:

- सभी लिंगों के लिए सुरक्षित और जिम्मेदार स्मार्टफोन उपयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।
- संवाद और संवेदीकरण के माध्यम से प्रतिगामी मानदंडों का मुकाबला करने के लिए समुदाय के नेताओं को शामिल करना।

महिलाओं को सशक्त बनाना:

- जमीनी स्तर पर संवैधानिक अधिकारों का दावा करने के लिए महिलाओं के समूहों, एसएचजी और स्थानीय संस्थानों का समर्थन करें।

निष्कर्ष

विवाहित महिलाओं द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग पर जाट पंचायत का प्रतिबंध केवल एक स्थानीय सामाजिक निर्णय नहीं है, बल्कि भारत में परंपरा और संवैधानिकता के बीच एक बड़े संघर्ष का लक्षण है। जबकि डिजिटल लत और बाल स्वास्थ्य के बारे में चिंताएं वैध हैं, उन्हें लिंग-भेदभावपूर्ण, गैर-संवैधानिक आदेशों के माध्यम से संबोधित करना मौलिक अधिकारों, महिला सशक्तिकरण और समावेशी विकास को कमजोर करता है। एक संवैधानिक लोकतंत्र सामाजिक सहमति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा को खत्म करने की अनुमति नहीं दे सकता है। संवैधानिक नैतिकता को बनाए रखना, राज्य की जवाबदेही को मजबूत करना और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देना यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि तकनीकी प्रगति गहरे बहिष्कार के बजाय वास्तविक सामाजिक सशक्तिकरण में तब्दील हो जाए।

UPSC Mains GS 4 : केस स्टडी प्रैक्टिस प्रश्न

प्रश्न : राजस्थान के एक ग्रामीण इलाके में, एक प्रमुख कृषि समुदाय से संबंधित एक जाति पंचायत ने हाल ही में एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें विवाहित महिलाओं और युवतियों को सार्वजनिक स्थानों जैसे शादियों, सामुदायिक समारोहों और पड़ोस के दौरे जैसे स्थानों पर स्मार्टफोन ले जाने पर रोक लगा दी गई है। पंचायत के बुजुर्गों ने मोबाइल की बढ़ती लत, बच्चों पर स्क्रीन टाइम के प्रतिकूल प्रभाव और "सामाजिक सद्भाव" और पारंपरिक मूल्यों को संरक्षित करने की आवश्यकता के आधार पर इस निर्णय को उचित ठहराया।

हालांकि इस प्रस्ताव को कोई कानूनी समर्थन नहीं है, लेकिन इसे मजबूत सामाजिक दबाव के माध्यम से लागू किया जा रहा है। फरमान का उल्लंघन करने वाली महिलाओं को सामाजिक बहिष्कार, सार्वजनिक शर्मिंदगी और पारिवारिक दबाव के खतरे का सामना करना पड़ता है। कई परिवारों ने सामाजिक प्रतिष्ठा के नुकसान के डर से, निजी तौर पर इससे असहमत होने के बावजूद आदेश का पालन किया है।

आप क्षेत्र के उप-मंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) के रूप में तैनात हैं। महिला अधिकार संगठनों और नागरिक समाज समूहों ने जिला प्रशासन से संपर्क किया है, तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए तर्क दिया है कि फरमान संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, पितृसत्ता को मजबूत करता है और डिजिटल लिंग विभाजन को गहरा करता है। साथ ही, कुछ समुदाय के नेताओं ने चेतावनी दी है कि कोई भी प्रत्यक्ष प्रशासनिक कार्रवाई सामाजिक शांति को भंग कर सकती है और राज्य मशीनरी के खिलाफ प्रतिरोध को भड़का सकती है।

आप व्यक्तिगत रूप से संवैधानिक मूल्यों, लैंगिक समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं, लेकिन आप क्षेत्र के नाजुक सामाजिक ताने-बाने और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के महत्व से भी अवगत हैं।

प्रश्न

1. उपरोक्त मामले में शामिल नैतिक मुद्दों की पहचान करें।
2. इसमें शामिल हितधारकों के परस्पर विरोधी मूल्यों और हितों की जांच करें।
3. एक व्यवस्थापक के रूप में, इस स्थिति से निपटने में आपके लिए कौन से विकल्प उपलब्ध हैं?
4. आप किस कार्रवाई को अपनाएंगे और क्यों? नैतिक आधार पर अपने निर्णय को सही ठहराएं।
5. सामाजिक सद्भाव सुनिश्चित करते हुए इस तरह के गैर-संवैधानिक सामाजिक आदेशों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या दीर्घकालिक उपाय किए जा सकते हैं?

भारत का स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन एक महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर रहा है जहां जलवायु महत्वाकांक्षा औद्योगिक नीति और भू-राजनीति के साथ प्रतिच्छेद करती है। दुर्लभ पृथ्वी तत्व (आरईई), हालांकि मात्रा में मामूली हैं, इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी), पवन टर्बाइन और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग किए जाने वाले उच्च-प्रदर्शन स्थायी चुम्बकों में उनकी भूमिका के कारण रणनीतिक रूप से अपरिहार्य हो गए हैं। घरेलू चुंबक निर्माण पर भारत की हालिया नीति पर ध्यान केंद्रित करना रणनीतिक कमजोरियों को कम करने के प्रयास को दर्शाता है। हालांकि, चुनौती पर्यावरणीय मानकों और शासन सिद्धांतों से समझौता किए बिना लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण में है।

पृष्ठभूमि और संदर्भ

- दुर्लभ पृथ्वी आपूर्ति श्रृंखलाएं अत्यधिक केंद्रित हैं, चीन न केवल खनन पर बल्कि अधिक गंभीर रूप से, रासायनिक शोधन और चुंबक निर्माण पर हावी है।
- असली अड़चन नियोडिमियम-आयरन-बोरॉन (NdFeB) स्थायी मैग्नेट है, न कि प्रति दुर्लभ पृथ्वी खनन।
- भारत ने सालाना 6,000 टन सिंटर्ड रेयर अर्थ मैग्नेट के उत्पादन के लिए एक एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए ₹7,280 करोड़ की योजना (2025 के अंत में) की घोषणा की है।
- भारत के घरेलू दुर्लभ पृथ्वी संसाधन काफी हद तक मोनाजाइट-असर वाली समुद्र तट रेत से जुड़े हुए हैं, जिसमें थोरियम भी होता है, जो इस क्षेत्र को परमाणु नियामक ढांचे से जोड़ता है।

भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के लिए महत्व

1. रणनीतिक और आर्थिक महत्व

- स्थायी चुम्बक इसके लिए आवश्यक हैं:
 - ईवी ट्रेक्शन मोटर्स
 - अपतटीय और तटवर्ती पवन टर्बाइन
 - उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा प्रणाली
- इस सेगमेंट में आयात निर्भरता भारत को भू-राजनीतिक झटके और कीमतों में उतार-चढ़ाव के लिए उजागर करती है।
- घरेलू चुंबक निर्माण ईवी, पवन घटकों और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण जैसे डाउनस्ट्रीम उद्योगों को उत्प्रेरित कर सकता है।

2. आपूर्ति श्रृंखला वास्तविकताएँ

- केवल खनन से आत्मनिर्भरता सुनिश्चित नहीं होती है।
- रासायनिक पृथक्करण और शोधन आरईई मूल्य श्रृंखला में वास्तविक चोक पॉइंट हैं।
- मिडस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्षमता के बिना, भारत घरेलू जमा की खोज के बाद भी निर्भर रहने का जोखिम उठाता है।

Magnetic moment

India must not undermine green compliance in its clean energy transition

At the end of 2025, rare earth elements sit in an awkward intersection between climate ambitions, industrial policy and geopolitics. They are not the most important minerals by volume in the clean energy economy but that has not stopped a small subset of them from becoming a gatekeeper for many of its important machines. The question today is not whether the world needs rare earths for its green transition but whether countries can build resilient and affordable supply chains without recreating the same environmental and governance problems in new places. The principal bottleneck is high-performance permanent magnets, especially neodymium-iron-boron magnets for EV motors and wind turbines. When supply falters, these elements, not all rare earths, pass the shock into economies. Likewise, countries can also announce new mines and still depend on others for chemical refining, which is to rare-earth elements what extraction is to crude oil, rather than mining itself. This structure is why China remains central to the supply chain even when deposits are found elsewhere.

This explains India's late-2025 focus on magnets rather than just mining. The ₹7,280-crore scheme to establish an integrated manufacturing ecosystem for 6,000 tonnes of sintered rare earth permanent magnets a year signals that if India can make magnets domestically, it will reduce a high-impact import exposure and create a platform for downstream manufacturing in EVs, wind components and advanced electronics. However, significant challenges lie upstream of this chain. A major domestic source for rare earths is monazite-bearing beach sands, which in India lie alongside thorium and other minerals relevant to the nuclear programme. The sector is thus pushed closer to a punctilious governance regime requiring close coordination across regulators and public sector entities, and which has to treat waste management and community engagement as core industrial inputs. Second, while the National Critical Mineral Mission has assigned a large number of exploration projects through 2031 to the Geological Survey, it needs the state to also translate knowledge of deposits into separating and manufacturing capacity, which demands regulatory clarity, reliable public financing, and credible enforcement. Third, India needs to augment midstream capacity, including by making magnet production bankable through long-term offtake from EV and electronics firms, and investing in process innovation that reduces dependence on the most constrained elements. The next phase of the green transition will reward countries that can scale supply chains, avoid undermining green compliance and distribute rather than concentrate risk. For India, that means turning policy and intent into industrial capacity, with environmental credibility baked in.

प्रमुख चुनौतियां

1. पर्यावरण और शासन की बाधाएँ

- मोनाजाइट निष्कर्षण में रेडियोधर्मी तत्व शामिल होते हैं, जिसके लिए आवश्यक है:
 - सख्त अपशिष्ट प्रबंधन प्रोटोकॉल
 - सामुदायिक व्यस्तता
 - अंतर-एजेंसी समन्वय
- पर्यावरणीय मानदंडों में कोई भी कमी भारत के हरित परिवर्तन की विश्वसनीयता को कमजोर कर सकती है।

2. नियामक और संस्थागत अड़चनें

- राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन ने 2031 तक कई अन्वेषण परियोजनाएं आवंटित की हैं।
- हालाँकि, अंतराल बने हुए हैं:
 - भूवैज्ञानिक ज्ञान को व्यावसायिक क्षमता में अनुवाद करना
 - निजी भागीदारी के लिए नियामक स्पष्टता
 - समय पर अनुमोदन और प्रवर्तन तंत्र

3. मिडस्ट्रीम और मैनुफैक्चरिंग गैप

- चुंबक निर्माण पूंजी-गहन और तकनीकी रूप से जटिल बना हुआ है।
- बैंक योग्य मांग की कमी निजी निवेश को रोकती है।
- नियोजिमियम जैसे विकृत तत्वों पर निर्भरता भेद्यता को बढ़ाती है।

आगे की राह

एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास: शोधन, मिश्र धातु और चुंबक निर्माण क्षमता बनाने के लिए खनन से आगे बढ़ें।

एक मुख्य इनपुट के रूप में पर्यावरणीय विश्वसनीयता : पर्यावरण अनुपालन, अपशिष्ट प्रबंधन और सामाजिक लाइसेंस को गैर-परक्राम्य औद्योगिक इनपुट के रूप में मानें।

सुनिश्चित उठाव और बाजार निर्माण : ईवी, नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं से दीर्घकालिक खरीद प्रतिबद्धताओं को सक्षम करना।

प्रक्रिया नवाचार और अनुसंधान एवं विकास : उन प्रौद्योगिकियों में निवेश करें जो:

दुर्लभ आरईई पर निर्भरता कम करें

पुनर्चक्रण और सामग्री दक्षता में सुधार

संस्थागत समन्वय : नियामकों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और राज्य सरकारों को एक पूर्वानुमानित शासन ढांचे के तहत संरेखित करना।

निष्कर्ष

वैश्विक हरित परिवर्तन का अगला चरण न केवल महत्वाकांक्षा को पुरस्कृत करेगा बल्कि संस्थागत क्षमता, पर्यावरणीय विश्वसनीयता और आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन को भी पुरस्कृत करेगा। दुर्लभ पृथ्वी चुम्बकों पर भारत का ध्यान रणनीतिक रूप से मजबूत है, लेकिन सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि नीतिगत इरादा टिकाऊ औद्योगिक क्षमता में तब्दील होता है या नहीं। अपनी स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं में मजबूत शासन और पर्यावरण अनुपालन को शामिल करके, भारत पिछले निष्कर्षण मॉडल को दोहराने से बच सकता है और वैश्विक हरित अर्थव्यवस्था में एक विश्वसनीय, जिम्मेदार खिलाड़ी के रूप में उभर सकता है।

UPSC प्रारम्भिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा बताता है कि चीन विश्व स्तर पर दुर्लभ पृथ्वी आपूर्ति श्रृंखला पर हावी क्यों है?

- A. दुर्लभ पृथ्वी जमा का विशेष स्वामित्व
- B. नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों पर एकाधिकार
- C. रासायनिक शोधन और चुंबक निर्माण में प्रभुत्व
- D. खनन क्षेत्र में सबसे कम श्रम लागत

उत्तर : c)

UPSC मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: भारत घरेलू दुर्लभ पृथ्वी मूल्य श्रृंखलाओं को विकसित करते समय रणनीतिक स्वायत्तता, पर्यावरणीय अनुपालन और आर्थिक व्यवहार्यता को कैसे संतुलित कर सकता है? आगे का रास्ता सुझाएं।

चीन और दक्षिण कोरिया की तुलना में विकास के स्तर पर 20 वीं शताब्दी की शुरुआत करने के बावजूद, भारत निरंतर विनिर्माण-आधारित औद्योगीकरण हासिल करने में विफल रहा है। जबकि पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं ने विनिर्माण के तेजी से विस्तार के माध्यम से अपने आर्थिक ढांचे को बदल दिया है, सकल घरेलू उत्पाद में भारत की विनिर्माण हिस्सेदारी स्थिर रही है और हाल के वर्षों में, सेवाओं को जमीन सौंप दी है। इस कमजोर प्रदर्शन का रोजगार सृजन, तकनीकी उन्नयन और आय वितरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

Why manufacturing has lagged in India

India's manufacturing sector underperforms compared to China and South Korea, partly due to public sector wages that raise costs and reduce competitiveness; despite growth in private industries like software and services, India sees limited technological upgrading, uneven wage growth, and increasing inequality

ECONOMIC NOTES

Rahul Menon

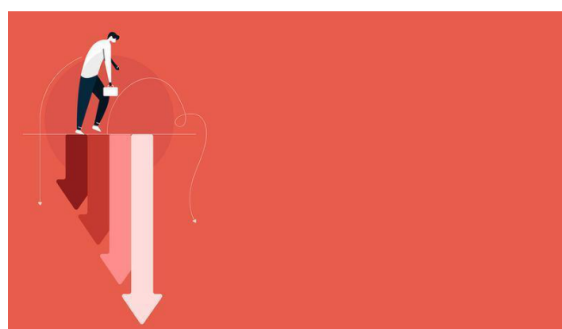
A reason why India has lagged behind certain non-Western economies – such as China and South Korea – despite starting from roughly equivalent positions early in the 20th century is the relative underperformance of its manufacturing sector. While China and South Korea have seen significant increases in manufacturing, the share of manufacturing in India's GDP has remained relatively constant over time and has recently lost ground to services.

In a recent discussion of his book *A Sixth of Humanity*, economist Arvind Subramanian explained why India has been unable to industrialise to the extent of China or South Korea. In his view, high government salaries drew workers away from manufacturing, raising prices and making it difficult for the sector to remain competitive, thus hindering its expansion. Mr. Subramanian used a theoretical framework known as the 'Dutch disease' to examine this outcome.

What is the Dutch disease?

The Dutch disease refers to a phenomenon where an economic windfall can often translate into negative outcomes in other sectors, such as manufacturing. It was initially coined to explain how the discovery of the Groningen gas fields in 1959 affected Dutch manufacturing.

The theory goes as follows: imagine an economy where a substantial holding of some natural resource – such as oil or another important mineral – is discovered. This would lead to a rise in wages as the sector bids away labour from other sectors, raising the economy-wide wage rate. Moreover, exports of the resource would lead to an appreciation of the currency, increasing imports and decreasing other price-sensitive exports. These effects would hurt domestic



GETTY IMAGES

manufacturing, which would be outcompeted by cheap imports from abroad and, at the same time, become relatively expensive in foreign markets.

But how would the Dutch disease apply to non-tradeable goods, such as government services? Suppose an economy expands its government sector and sets high wages for its workers. Manufacturing would then find it hard to meet these wages at its given level of productivity. Increased demand from government employees – due to higher incomes – would raise prices of domestic goods. Under a regime of free trade, this would boost demand for cheaper imports, reducing demand for domestically manufactured goods even if the nominal exchange rate does not change. The real exchange rate would appreciate due to higher domestic prices.

The Dutch disease model can be used to outline such a process in which the expansion of one sector leads to reduced outcomes for other sectors through price movements. In this model, the Indian State's policy choices to raise salaries in the public sector negatively affected manufacturing and can be seen as one of the reasons why the process of structural transformation in India has stagnated.

Question of technology

One problem is that the framework was initially used to analyse the effects of a windfall discovery, not the effects of policy. The relatively higher salaries cannot easily be compared to the discovery of an oil field, because one is a conscious political decision undertaken by a democratically elected government, while the other is a natural endowment.

One could argue that while the nature of the economies – one with a strong public sector and one with a natural resource endowment – is drastically different, the effects are the same and operate through the same channel of a real exchange rate appreciation. But turning the question around offers another way to view the problem. If high government salaries were initially a problem, why did technological growth not occur over the long run to make manufacturing more productive to sustain higher wages?

The theory of 'induced innovation' holds that labour scarcity and high wages can induce technological and capital-biased growth. The economist Sir John Habakkuk hypothesised that 19th-century Britain grew faster than the U.S. because of its relative scarcity of land

and labour. Economic historian Robert C. Allen states that Britain's high wages ensured the need for technological innovation, which led to the Industrial Revolution occurring there rather than on the continent. In more contemporary times, Nobel laureate Daron Acemoglu used this to explain why automation led to faster productivity and wage growth in economies like Germany, Japan and South Korea – with an ageing labour force – while automation restricts wages in countries like the U.S., with a larger labour force.

Limits of wages

An analysis of India's development story must focus on the nature of technological change and on why the private sector growth has not translated into rising wages. The question is stark in India's fast-growing services and software industries. Entry-level salaries at major Indian software giants have shown little growth since the 2000s, despite the retreat of the State, the proliferation of markets and the rise of private sector billionaires.

A case can be made that India's modern software unicorns – such as Swiggy, Zomato, Blinkit and Ola – rely on India's abundant labour reserves rather than representing genuine technological upgradation.

The Indian private sector has undoubtedly shown significant levels of dynamism and growth. But this growth has been lop-sided, as the rapid increase in inequality has shown us. If public sector salaries kept wages higher earlier, it is legitimate to ask why manufacturing has not responded with an adequate level of technological change to ensure productivity growth. Did government intervention prevent the ability to adopt new technology? Or did manufacturing become addicted to the reserves of cheap labour and not invest in technological upgradation, leading to a relative stagnation over time?

Rahul Menon is associate professor at O.P. Jindal Global University

THE GIST

India has lagged behind China and South Korea because the share of manufacturing in India's GDP has remained relatively constant and has recently lost ground to services, limiting productivity and income growth.

High government salaries drew workers away from manufacturing, raised economy-wide wages and prices, and led to a real exchange rate appreciation, making manufacturing less competitive.

Despite private sector dynamism, manufacturing failed to respond with adequate technological upgradation; instead, growth relied on abundant labour reserves, leading to lop-sided growth, rising inequality, and stagnation in wages and productivity.

पृष्ठभूमि

- विनिर्माण ऐतिहासिक रूप से संरचनात्मक परिवर्तन का इंजन रहा है, जो बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन और उत्पादकता वृद्धि को सक्षम बनाता है।
- भारत में, सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण का हिस्सा लगभग 15-17% है, जबकि चीन और दक्षिण कोरिया के विपरीत, जहां यह चरम औद्योगीकरण के दौरान 25-30% को पार कर गया था।
- अर्थशास्त्री अरविंद सुब्रमण्यन ने अपनी पुस्तक ए सिक्स्थ ऑफ ह्यूमैनिटी में इस अंतराल का श्रेय आंशिक रूप से सार्वजनिक क्षेत्र की वेतन नीतियों को दिया है, जो डच बीमारी के लेंस के माध्यम से इस घटना का विश्लेषण करते हैं।

तर्क को समझना: डच रोग और भारत

1. डच रोग ढांचे का अनुप्रयोग

- परंपरागत रूप से, डच रोग बताता है कि कैसे एक संसाधन अप्रत्याशित मजदूरी बढ़ाता है और वास्तविक विनिमय दर की सहायता करता है, विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता को नुकसान पहुंचाता है।
- भारत के मामले में, तर्क यह है कि उच्च सार्वजनिक क्षेत्र का वेतन:
 - श्रमिकों को विनिर्माण से दूर किया
 - अर्थव्यवस्था-व्यापी वेतन उम्मीदों में वृद्धि
 - गैर-व्यापार योग्य वस्तुओं की घरेलू कीमतों में वृद्धि
- इससे वास्तविक विनिमय दर में वृद्धि हुई, जिससे नाममात्र मुद्रा में वृद्धि के बिना भी घरेलू विनिर्माण की प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो गई।

2. विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रभाव

- अपेक्षाकृत कम उत्पादकता स्तरों पर काम करने वाली विनिर्माण कंपनियां सार्वजनिक क्षेत्र के वेतन की बराबरी नहीं कर सकतीं।
- बढ़ती घरेलू मांग को आयात के माध्यम से तेजी से पूरा किया गया, जिससे घरेलू विनिर्माण और कमजोर हो गया।
- परिणामस्वरूप, भारत का संरचनात्मक परिवर्तन रुक गया।

स्पष्टीकरण की सीमाएँ

1. पॉलिसी विकल्प बनाम प्राकृतिक अप्रत्याशित लाभ

- प्राकृतिक संसाधनों की खोजों के विपरीत, सार्वजनिक क्षेत्र की मजदूरी जानबूझकर राजनीतिक निर्णय हैं।
- यह शास्त्रीय डच रोग के साथ प्रत्यक्ष सादृश्य को कमजोर करता है, जिसे नीति-प्रेरित परिणामों की व्याख्या करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था।

2. प्रेरित तकनीकी नवाचार की विफलता

- आर्थिक सिद्धांत बताता है कि उच्च मजदूरी को नवाचार, पूंजी को मजबूत करने और उत्पादकता वृद्धि को प्रेरित करना चाहिए।
- ऐतिहासिक और समकालीन साक्ष्य:
 - ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति
 - जर्मनी, जापान और दक्षिण कोरिया में स्वचालन के नेतृत्व वाली उत्पादकता वृद्धि
- हालांकि, भारत में, विनिर्माण ने पर्याप्त तकनीकी उन्नयन के साथ प्रतिक्रिया नहीं दी, जो गहरी संरचनात्मक बाधाओं को दर्शाता है।

भारत में प्रौद्योगिकी, मजदूरी और असमानता

- भारत का निजी क्षेत्र का विकास क्षेत्रीय रूप से विषम रहा है:
 - सेवाओं और सॉफ्टवेयर का तेजी से विस्तार हुआ
 - उत्पादकता वृद्धि में विनिर्माण पिछड़ गया

- यहां तक कि तेजी से बढ़ती आईटी और प्लेटफॉर्म-आधारित फर्मों के पास भी है:
 - स्थिर प्रवेश स्तर की मजदूरी
 - प्रचुर मात्रा में सस्ते श्रम पर बहुत अधिक निर्भर
- कई डिजिटल "यूनिकॉर्न" सीमांत तकनीकी नवाचार के बजाय श्रम-गहन एकत्रीकरण मॉडल का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- इसका परिणाम यह हुआ है:
 - कमजोर वेतन वृद्धि
 - सीमित रोजगार सृजन
 - बढ़ती आय और धन असमानता

मुख्य संरचनात्मक मुद्दे

- सस्ते श्रम पर निर्भरता ने मशीनीकरण और स्वचालन के लिए प्रोत्साहन कम किया
- पूर्वी एशिया की तुलना में कमजोर औद्योगिक नीति समन्वय
- विनिर्माण में प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए सीमित राज्य समर्थन
- मजबूत विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र और आपूर्तिकर्ता नेटवर्क का अभाव

आगे की राह

उत्पादकता आधारित विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करें

- स्वचालन और पूंजी को गहरा करने को प्रोत्साहित करें
- उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकियों को अपनाने में सहायता करें

औद्योगिक नीति को पुनर्संतुलित करें

- सेवाओं के नेतृत्व वाले विकास से आगे बढ़ें
- क्षेत्र-विशिष्ट विनिर्माण रणनीतियों को मजबूत करना

कौशल और प्रौद्योगिकी संबंध

- औद्योगिक उन्नयन के साथ कौशल पहल को संरेखित करें
- अनुसंधान एवं विकास के नेतृत्व वाले विनिर्माण समूहों को बढ़ावा देना

उत्पादकता के साथ मजदूरी वृद्धि

- सुनिश्चित करें कि मजदूरी में वृद्धि उत्पादकता लाभ द्वारा समर्थित है
- अनौपचारिक और कम वेतन वाले श्रम पर अत्यधिक निर्भरता को रोकना

निष्कर्ष

भारत के विनिर्माण ठहराव को केवल सार्वजनिक क्षेत्र के वेतन या डच रोग की गतिशीलता से नहीं समझाया जा सकता है। गहरा मुद्दा बढ़ती मजदूरी और निजी क्षेत्र के विस्तार के बावजूद विनिर्माण में निरंतर तकनीकी परिवर्तन को प्रेरित करने में विफलता में निहित है। उत्पादकता आधारित औद्योगीकरण के बिना, भारत में रोजगार रहित विकास, बढ़ती असमानता और

समय से पहले विऔद्योगीकरण द्वारा चिह्नित विकास पथ का जोखिम है। समावेशी और सतत आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए विनिर्माण-संचालित संरचनात्मक परिवर्तन पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है।

UPSC प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न : 'डच रोग' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जहां अर्थव्यवस्था के एक क्षेत्र का विस्तार मूल्य और मजदूरी तंत्र के माध्यम से अन्य व्यापार योग्य क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
2. इसमें आवश्यक रूप से नाममात्र विनिमय दर की सराहना शामिल है।
3. यह प्राकृतिक संसाधन की खोज के अभाव में भी काम कर सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है?

- A. केवल 1 और 2
- B. केवल 1 और 3
- C. केवल 2 और 3
- D. 1, 2 और 3

उत्तर : b)

UPSC मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न : डच रोग की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में विनिर्माण में भारत के खराब प्रदर्शन को समझाने के लिए इसे किस हद तक लागू किया जा सकता है?

तेजी से बंदरगाह आधारित विकास और बढ़ते तटीय व्यापार से प्रेरित भारत के बढ़ते समुद्री पदचिह्न ने एक मजबूत और एकीकृत बंदरगाह सुरक्षा वास्तुकला की आवश्यकता को तेज कर दिया है। इस संदर्भ में, मर्चेण्ट शिपिंग अधिनियम, 2025 के तहत बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो (बीओपीएस) की स्थापना एक महत्वपूर्ण संस्थागत सुधार का प्रतीक है जिसका उद्देश्य तटीय सुरक्षा को मजबूत करना, नियामक निरीक्षण सुनिश्चित करना और भारत के बंदरगाहों को वैश्विक सुरक्षा मानकों के साथ संरेखित करना है।

What is the Bureau of Port Security and its role?

What challenges in coastal security does India face and how will BoPS address them?

Saeed Pande

The story so far:

The Centre has constituted the Bureau of Port Security (BoPS) as a statutory body under Section 13 of the newly established Merchant Shipping Act 2025. Modelled on the Bureau of Civil Aviation Security, it will function under the Ministry of Ports, Shipping and Waterways and will be responsible for regulatory oversight functions relating to the security of ships and port facilities.

Why was BoPS created?

Currently, coastal security responsibilities are shared among multiple agencies such as the Coast Guard, Central Industrial Security Force (CISF), State maritime police, and the Navy. This leads to challenges in coordination and communication, and also leads to possible security gaps. The BoPS will be a single statutory body for regulatory oversight and coordination.

The BoPS will also address security

concerns such as maritime terrorism, smuggling of arms, drug trafficking, human trafficking and other illicit trafficking, poaching, illegal migration via waterways, piracy, and cybersecurity threats. It is expected to include a dedicated division to protect port IT infrastructure from digital threats, with a special focus on cybersecurity, and the collection and exchange of security-related information. The BoPS will monitor, counter, and deter such intrusions and coordinate with national cybersecurity agencies.

As a statutory body under the Merchant Shipping Act, the BoPS will have the legal authority to enforce compliance with international standards such as the International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code. Under the BoPS, the CISF is designated as a recognised Security Organisation to prepare standardised plans, conduct security assessments, and train private agencies across all major and non-major ports. Security measures are to be implemented in a graded manner.

What is India's maritime growth so far?

According to the Ministry of Shipping, Ports and Waterways, the last decade has been transformative in terms of Maritime surge. Cargo growth increased from 974 million tonnes (MMT) in 2014 to 1,594 MMT in 2025. Port capacity has expanded by 57%, enhancing efficiency and volume. Ship turnaround time has reduced by half, to 48 hours, aligning with global standards. Coastal shipping volumes rose 118%, reflecting stronger domestic connectivity, while cargo movement through inland waterways surged eightfold from 18.1 MMT in 2014 to 145.5 MMT by 2025, unlocking new logistic corridors. Nine Indian ports featured in the World Bank's Container Port Performance Index, signalling rising international recognition.

In 2021, India launched its strategy for Maritime India Vision 2030 to ensure a safe, sustainable, and secure maritime future. At the top of the 2030 Maritime vision list is 'to develop best-in-class port infrastructure'. The BoPS has been

defined in line with this vision.

How have port laws been modernised?

These developments called for a revival and strengthening of Port security infrastructure, defined security measures and conservation of the coastal environment with an impetus for ease of business. This led to the replacement of the century-old Indian Ports Act of 1908 with the Indian Ports Act of 2025, along with additional legislation like the Coastal Shipping Act of 2025, the Modernised Merchant Shipping Legislation 2025, and the Bureau of Port Security 2025. These laws aim to modernise the framework for coastal trade, encourage Indian ownership and operation of vessels, simplify licensing and regulatory processes, and promote cost-efficient and eco-friendly sea transport.

What criticisms exist?

The new legislation has granted the Union government more authority over non-major (State-owned) ports. Some coastal States have criticised it as a "silent cost to maritime federalism." The Indian Ports Act has also been criticised for granting port officers, conservators, and health officers extensive powers for entry and inspection without clearly specifying judicial procedural safeguards. These criticisms are aimed at the legislation rather than BoPS itself.

Saeed Pande is a freelance writer with a focus on politics, current affairs, international relations, and geopolitics

THE GIST

The Centre has set up the Bureau of Port Security under the Merchant Shipping Act 2025 to ensure regulatory oversight, coordination, and compliance with international security standards amid growing maritime and cybersecurity threats.

India's maritime sector has seen a sharp surge in cargo and port capacity, alongside new port laws that have also drawn criticism over increased Union control of non-major ports.

पृष्ठभूमि: BoPS क्यों बनाया गया था?

- भारत में 7,500+ किमी की तटरेखा, 12 प्रमुख बंदरगाह और 200 से अधिक गैर-प्रमुख बंदरगाह हैं।
- तटीय और बंदरगाह सुरक्षा जिम्मेदारियां पहले अलग-अलग थीं:
 - भारतीय तटरक्षक बल
 - भारतीय नौसेना
 - केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ)
 - राज्य समुद्री पुलिस

इस बहु-एजेंसी ढांचे के परिणामस्वरूप अक्सर निम्न होते हैं:

- ओवरलैपिंग जनादेश
- समन्वय अंतराल
- बंदरगाहों पर असंगत सुरक्षा मानक
- बीओपीएस का गठन पूरे भारत में बंदरगाह और जहाज सुरक्षा के नियामक निरीक्षण, समन्वय और मानकीकरण प्रदान करने के लिए एक एकल वैधानिक प्राधिकरण के रूप में किया गया है।

भारत का समुद्री विकास और सुरक्षा अनिवार्यता

- कार्गो हैंडलिंग 974 एमएमटी (2014) से बढ़कर 1,594 एमएमटी (2025) हो गई
- बंदरगाह क्षमता में 57 प्रतिशत की वृद्धि हुई
- जहाज के टर्नअराउंड समय को घटाकर 48 घंटे कर दिया गया
- तटीय शिपिंग में 118% की वृद्धि हुई
- अंतर्देशीय जलमार्ग कार्गो आठ गुना बढ़ गया
- विश्व बैंक के कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक में नौ भारतीय बंदरगाहों को शामिल किया गया
- इस उछाल ने बंदरगाहों को लॉजिस्टिक्स हब से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे तक बढ़ा दिया है, जिससे वे भौतिक और डिजिटल दोनों खतरों के लिए आकर्षक लक्ष्य बन गए हैं।

भारत के सामने प्रमुख तटीय सुरक्षा चुनौतियां

1. समुद्री आतंकवाद और तोड़फोड़

- असममित युद्ध के लिए बंदरगाह उच्च-मूल्य वाले लक्ष्य बने हुए हैं।
- पिछले अनुभव (उदाहरण के लिए, समुद्र में होने वाली आतंकी घुसपैठ) कमजोरियों को रेखांकित करते हैं।

2. तस्करी और अवैध तस्करी

- हथियार, नशीले पदार्थ, मानव तस्करी और वन्यजीव अवैध शिकार झरझरा तटीय क्षेत्रों का शोषण करते हैं।
- तटीय व्यापार में वृद्धि से निरीक्षण और निगरानी चुनौतियाँ कई गुना बढ़ जाती हैं।

3. अवैध प्रवासन और समुद्री डकैती

- सीमा पार घुसपैठ और समुद्री डकैती के लिए अनियमित जलमार्गों का दुरुपयोग किया जा सकता है।

4. साइबर सुरक्षा खतरे

- बंदरगाह संचालन के डिजिटलीकरण से पता चलता है:
 - कार्गो प्रबंधन प्रणाली
 - पोत ट्रैकिंग
 - सीमा शुल्क और रसद नेटवर्क
- साइबर हमले भौतिक घुसपैठ के बिना राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर सकते हैं।

5. समान सुरक्षा मानकों का अभाव

- प्रमुख और गैर-प्रमुख बंदरगाहों के बीच सुरक्षा तैयारियों में भिन्नता।

बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो की भूमिका और कार्य

1. वैधानिक नियामक प्राधिकरण

- मर्चेन्ट शिपिंग अधिनियम, 2025 की धारा 13 के तहत स्थापित
- अंतर्राष्ट्रीय जहाज और बंदरगाह सुविधा सुरक्षा (आईएसपीएस) कोड के अनुपालन को लागू करने का अधिकार दिया गया

2. एकल-बिंदु समन्वय

- समन्वय करने वाले नोडल निकाय के रूप में कार्य करता है:
 - सीआईएसएफ
 - बंदरगाह प्राधिकरण
 - राज्य एजेंसियां
 - राष्ट्रीय समुद्री और साइबर सुरक्षा संस्थान

3. सुरक्षा उपायों का मानकीकरण

- सीआईएसएफ को एक मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन के रूप में नामित किया गया
- समान सुरक्षा योजना तैयार करना
- समय-समय पर सुरक्षा आकलन और ऑडिट
- निजी सुरक्षा एजेंसियों का प्रशिक्षण और प्रमाणन

4. साइबर सुरक्षा और सूचना साझाकरण

- इसके लिए समर्पित साइबर सुरक्षा प्रभाग:
 - पोर्ट आईटी बुनियादी ढांचे की सुरक्षा करना
 - डिजिटल घुसपैठ की निगरानी
 - राष्ट्रीय साइबर एजेंसियों के साथ खुफिया जानकारी साझा करना

5. श्रेणीबद्ध सुरक्षा कार्यान्वयन

- सुरक्षा उपायों की जोखिम-आधारित तैनाती
- बंदरगाहों पर एक आकार-फिट-सभी दृष्टिकोण से बचता है

सीमा प्रशासन के आधार पर कानूनी और संस्थागत सुधार

- भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 1908 को भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 2025 से प्रतिस्थापित करना

का परिचय:

- तटीय नौवहन अधिनियम, 2025
- आधुनिक मर्चेन्ट शिपिंग विधान, 2025

उद्देश्य:

- व्यापार करने में आसानी
- पर्यावरण सुरक्षा उपाय
- भारतीय नौवहन को बढ़ावा देना
- एकीकृत बंदरगाह शासन

आलोचनाएँ और चिंताएँ**संघवाद के मुद्दे:**

- तटीय राज्यों का तर्क है कि गैर-प्रमुख बंदरगाहों पर संघ का नियंत्रण बढ़ता है जो समुद्री संघवाद को कमजोर करता है।

नागरिक स्वतंत्रता संबंधी चिंताएँ:

- स्पष्ट रूप से परिभाषित न्यायिक सुरक्षा उपायों के बिना बंदरगाह अधिकारियों के लिए निरीक्षण और प्रवेश शक्तियों का विस्तार किया गया है।
- ये चिंताएँ मुख्य रूप से व्यापक बंदरगाह कानून पर निर्देशित हैं, न कि बीओपीएस के सुरक्षा जनादेश पर।

आगे की राह**सहकारी संघवाद:**

- सुरक्षा योजना में तटीय राज्यों के साथ संस्थागत परामर्श।

प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय स्पष्ट करें:

- उचित प्रक्रिया और पारदर्शिता के साथ सुरक्षा प्रवर्तन को संतुलित करें।

प्रौद्योगिकी-संचालित सुरक्षा:

- एआई-सक्षम निगरानी, एकीकृत तटीय रडार नेटवर्क और साइबर लचीलापन।

क्षमता निर्माण:

- बंदरगाह सुरक्षा कर्मियों का निरंतर प्रशिक्षण।

पर्यावरण-सुरक्षा संतुलन:

- सुनिश्चित करें कि सुरक्षा विस्तार तटीय पारिस्थितिकी से समझौता नहीं करता है।

निष्कर्ष

बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो भारत के समुद्री सुरक्षा ढांचे को उसकी बढ़ती आर्थिक और रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं के साथ संरेखित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है। एकीकृत निरीक्षण प्रदान करके, वैश्विक सुरक्षा मानकों को लागू करके और उभरते साइबर और गैर-पारंपरिक खतरों को संबोधित करके, बीओपीएस भारत की तटीय सुरक्षा संरचना को

मजबूत करता है। हालांकि, इसकी दीर्घकालिक प्रभावशीलता सहकारी संघवाद, प्रक्रियात्मक स्पष्टता और मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के तहत बंदरगाह आधारित विकास के साथ सुरक्षा के निर्बाध एकीकरण पर निर्भर करेगी।

UPSC प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न : बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो (बीओपीएस) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसे मर्चेन्ट शिपिंग अधिनियम, 2025 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया है।
2. यह गृह मंत्रालय के तहत कार्य करता है।
3. यह भारत में अंतर्राष्ट्रीय जहाज और बंदरगाह सुविधा सुरक्षा (आईएसपीएस) कोड को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 3
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: b)

UPSC मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न : बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो (BoPS) की स्थापना भारत में केंद्रीकृत समुद्री सुरक्षा शासन की ओर एक बदलाव का प्रतीक है। समुद्री संघवाद से संबंधित चिंताओं की जांच करते समय इसके महत्व पर चर्चा करें। (150 शब्द)

New labour codes, the threats to informal workers

Unions and workers' organisations have been raising objections against the new labour codes of 2019 and 2020. The four codes – they concern industrial relations, wages, social security and occupational health and safety of workers – were passed without a tripartite consultation between workers, employers and government representatives at the Indian Labour Conference (ILC). As implementation of the codes begin, the hard-won labour rights of workers across sectors are either threatened or destroyed. While the impact on workers in the organised sector is rightfully being discussed, debated and documented, the codes also significantly endanger unorganised sector workers, who are estimated to constitute over 90% of India's workforce and producing 65% of its GDP. As Tamil Nadu deliberates on issuing rules for the Social Security Code, the serious dangers posed by the Codes to unorganised workers in particular must be highlighted.

On the Codes

The Union Government claims that the codes are an attempt to "consolidate" and codify existing labour laws and "universalise" social security for workers. However, the claims of universalisation and consolidation are myths. Unorganised workers have been mostly left out of consideration in all codes except the one concerning social security. Alongside, in the name of consolidation, existing protections for them under other laws such as the Building and Other Construction Workers (BOCW) Act, 1996, have been threatened or entirely repealed. For instance, about 180 rules have been laid out under the BOCW Act to ensure worker safety at construction sites. These are now entirely missing in the central rules issued for the new Occupational Safety, Health and Working Conditions (OSHCW) Code. This is a dangerous sign given the hazardous nature of labour and the high number of deaths in the construction sector.



R. Geetha is Adviser to the Unorganized Workers Federation (UWF)



Priti Narayan is Assistant Professor in the Department of Geography at the University of British Columbia

Unorganised workers have been left out of consideration in all the codes except the one that concerns social security

The OSHWC code has also replaced an existing system of inspection with a process that is web-based, which cannot be an effective means of ensuring the safety of the workplace or minimum wage implementation. This is in violation of ILO Convention 81 which is ratified by India. Unorganised workers can also contract diseases from prolonged manual work and exposure across several sectors. Silicosis is very prevalent in the construction sector, while agricultural workers have a high incidence of cancer from pesticide use, while salt workers face chronic eye, skin and kidney problems. There is no concern for these realities of informal workers and their working conditions in the OSHWC. This negligence stands in violation of ILO Convention 161, which calls for a national policy on occupational health services for all workers and mandates identification, treatment and rehabilitation in the event of an occupational disease. In threatening and repealing sector-specific laws for workers such as the BOCW Act, the codes foreclose a serious consideration of the occupational health of informal workers. Given that the Employees' State Insurance (ESI) is not available to them, informal workers will have no state recognition or measures to address their occupational health and safety concerns. Threats to welfare boards and funds In the Social Security (SS) Code, organised workers seem to be given some social security benefits, while informal workers are to receive vaguely defined "welfare schemes". Also notable is the abolition of various cesses as part of the Goods and Services Tax reforms, with no replacement of the cesses collected to provide for the welfare of workers in the beedi, salt, mining and other sectors. This implies that there are no guaranteed funds, raised either from employers in particular

sectors or offered by the Union government, to provide for the welfare of informal sector workers. In fact, the SS Code sets up one welfare board for all unorganised workers, with no imagination of the various sectors that informal workers can and do work in, except for construction and gig work. Even in the construction sector, the implementation of the now-centralised e-Shram registration system creates a possibility for the central government to take over accrued funds raised for workers' welfare – estimated to be of the order of ₹1 lakh crore. As is, in Tamil Nadu, the SS Code stands to threaten the dissolution of all existing 39 sector-specific boards established in Tamil Nadu. There are no saving clauses for these State-level welfare boards and the protections they offer, including old age pensions, maternity assistance and educational assistance for workers' children. This reality, highlighted consistently by unions and worker movements, is perhaps the main reason why Tamil Nadu continues to deliberate on issuing rules for the SS Code. What needs to be done Some States including Andhra Pradesh have closed down their welfare boards in response to the Codes. Tamil Nadu has a strong architecture for workers welfare under the Tamil Nadu Manual Workers Act, 1982, painstakingly built through worker and union demands and advocacy. It is estimated that there are three crore informal workers in the State, and about two crore workers registered across the various welfare boards. To ensure the welfare of these workers, the State government must protect its welfare boards and State-level labour legislation at all costs. Like Kerala, Tamil Nadu must refuse to implement the codes and notify rules, and, instead, push for saving clauses of existing State-level welfare infrastructure.

GS पेपर 2: शासन

संघ लोक सेवा आयोग मुख्य अभ्यास प्रश्न : "भारत में श्रम कानून सुधारों का उद्देश्य विनियमन को सरल बनाना और व्यापार करने में आसानी में सुधार करना है, लेकिन अनौपचारिक कार्यबल को छोड़कर जोखिम है। इस बात की गंभीरता से जांच कीजिए कि नए श्रम संहिताएं भारत में अनौपचारिक श्रमिकों को कैसे प्रभावित करती हैं। समावेशी और न्यायसंगत श्रम सुधार सुनिश्चित करने के लिए किन सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है? (150 शब्द)

संदर्भ :

2019 और 2020 के बीच अधिनियमित भारत के नए श्रम संहिताओं को श्रम कानूनों को मजबूत करने, व्यापार करने में आसानी में सुधार और सामाजिक सुरक्षा को सार्वभौमिक बनाने के उद्देश्य से परिवर्तनकारी सुधारों के रूप में पेश किया गया था। हालांकि, जैसे-जैसे राज्य कार्यान्वयन की प्रक्रिया शुरू करते हैं, अनौपचारिक श्रमिकों पर उनके प्रभाव के बारे में गंभीर चिंताएं उभर कर सामने आई हैं, जो भारत के कार्यबल का 90% से अधिक हैं और सकल घरेलू उत्पाद में लगभग दो-तिहाई योगदान करते हैं। सुरक्षा प्रदान करने के बजाय, श्रम संहिताएं असंगठित श्रमिकों के लिए लंबे समय से चली आ रही सुरक्षा उपायों को कमजोर करने का जोखिम उठाती हैं।

पृष्ठभूमि: नए श्रम संहिताएं

- चार श्रम संहिताएं अधिनियमित की गईं:
 - वेतन पर कोड
 - औद्योगिक संबंध संहिता
 - सामाजिक सुरक्षा संहिता
 - व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति (OSHCW) कोड
- इन संहिताओं ने लगभग 29 मौजूदा श्रम कानूनों को बदल दिया।
- स्थापित श्रम शासन मानदंडों से हटते हुए, भारतीय श्रम सम्मेलन में त्रिपक्षीय परामर्श के बिना संहिताओं को पारित किया गया था।

अनौपचारिक श्रमिकों को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दे**1. क्षेत्र-विशिष्ट कानूनी सुरक्षा का क्षरण**

- भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (बीओसीडब्ल्यू) अधिनियम, 1996 जैसे कानून, जिनमें विस्तृत सुरक्षा और कल्याण प्रावधान शामिल थे, को कमजोर या निरस्त कर दिया गया है।
- BOCW के तहत लगभग 180 सुरक्षा-संबंधी नियमों में OSHCW कोड में कोई समकक्ष सुरक्षा उपाय नहीं पाए गए हैं।
- यह विशेष रूप से निर्माण और अन्य खतरनाक क्षेत्रों में उच्च दुर्घटना और मृत्यु दर को देखते हुए चिंताजनक है।

2. निरीक्षण और प्रवर्तन तंत्र का कमजोर होना

- OSHCW कोड शारीरिक श्रम निरीक्षण को वेब-आधारित, जोखिम-आधारित निरीक्षणों से बदल देता है।
- यह निम्नलिखित के ऑन-ग्राउंड प्रवर्तन को कमजोर करता है:
 - न्यूनतम मजदूरी
 - कार्यस्थल सुरक्षा
- इस तरह के कमजोर पड़ने का अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन 81 के साथ संघर्ष करता है, जो प्रभावी श्रम निरीक्षण प्रणालियों को अनिवार्य करता है।

3. अनौपचारिक श्रमिकों के व्यावसायिक स्वास्थ्य की उपेक्षा

- अनौपचारिक श्रमिकों को गंभीर व्यावसायिक स्वास्थ्य जोखिमों का सामना करना पड़ता है:
 - निर्माण और खनन श्रमिकों के बीच सिलिकोसिस
 - कीटनाशकों के संपर्क में आने से कृषि श्रमिकों में कैंसर

- नमक श्रमिकों के बीच पुरानी बीमारियां
- OSHWC कोड व्यावसायिक रोगों को पर्याप्त रूप से पहचानना, निगरानी या क्षतिपूर्ति नहीं करता है।
- यह आईएलओ कन्वेंशन 161 के विपरीत है, जो सभी श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य नीति का आह्वान करता है।

सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत खतरे

1. अस्पष्ट कल्याण अधिकार

- जबकि संगठित श्रमिकों को परिभाषित सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त होते हैं, अनौपचारिक श्रमिकों को "कल्याणकारी योजनाओं" का वादा किया जाता है।
- इसकी कोई वैधानिक गारंटी नहीं है:
 - कवरेज
 - पर्याप्त धन
 - समय पर डिलीवरी

2. कल्याण उपकरणों का उन्मूलन

- जीएसटी के बाद क्षेत्र-विशिष्ट उपकरण (बीड़ी, खनन, नमक, आदि) को समाप्त कर दिया गया है।
- किसी वैकल्पिक वित्त पोषण तंत्र का आश्वासन नहीं दिया गया है।
- यह अनौपचारिक श्रमिक कल्याण को विवेकाधीन बजटीय सहायता पर निर्भर करता है।

3. कल्याण बोर्डों का केंद्रीकरण और कमजोर होना

- सामाजिक सुरक्षा संहिता में सभी असंगठित श्रमिकों के लिए एक एकल कल्याण बोर्ड का प्रस्ताव है।
- यह क्षेत्रीय विविधता और विशिष्ट जोखिमों को नजरअंदाज करता है।
- तमिलनाडु के 39 क्षेत्र-विशिष्ट बोर्डों जैसे राज्य-स्तरीय कल्याण बोर्डों को संभावित विघटन का सामना करना पड़ रहा है।
- ई-श्रम जैसे केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म बड़े संचित कल्याण निधियों पर संभावित केंद्रीय नियंत्रण के बारे में चिंता पैदा करते हैं।

संघवाद और राज्य-स्तरीय चिंताएँ

- श्रम एक समवर्ती सूची का विषय है, जिसके लिए सहकारी संघवाद की आवश्यकता होती है।
- तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों ने राज्य कानून के माध्यम से मजबूत कल्याणकारी ढांचे का निर्माण किया है।
- मौजूदा राज्य कानूनों के लिए बचत खंडों की अनुपस्थिति निम्नलिखित को कमजोर करती है:
 - राज्य की स्वायत्तता
 - संदर्भ-विशिष्ट कल्याण मॉडल
- कुछ राज्यों ने पहले ही कल्याण बोर्डों को भंग कर दिया है, जो श्रम संरक्षण में नीचे की ओर दौड़ का संकेत देता है।

आगे की राह

त्रिपक्षीय संवाद बहाल करना: आम सहमति निर्माण के लिए एक मंच के रूप में भारतीय श्रम सम्मेलन को पुनर्जीवित करना।

बचत खंड डालें: मौजूदा राज्य-स्तरीय कल्याण बोर्डों और क्षेत्र-विशिष्ट कानून की रक्षा करें।

निरीक्षण तंत्र को मजबूत करें: अनिवार्य भौतिक निरीक्षण के साथ डिजिटल उपकरणों को संयोजित करें।

अनौपचारिक श्रमिकों के लिए गारंटी फंडिंग: वैधानिक वित्त पोषण तंत्र के साथ क्षेत्रीय उपकरणों को फिर से शुरू करना या प्रतिस्थापित करना।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों के साथ संरेखित करें: श्रम निरीक्षण और व्यावसायिक स्वास्थ्य पर अनुसमर्थित ILO सम्मेलनों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

निष्कर्ष

नए श्रम संहिता, अपने वर्तमान स्वरूप में, क्षेत्र-विशिष्ट सुरक्षा को खत्म करके, प्रवर्तन को कमजोर करके और सुरक्षा उपायों के बिना कल्याणकारी तंत्र को केंद्रीकृत करके भारत के अनौपचारिक कार्यबल की भेद्यता को गहरा करने का जोखिम उठाते हैं। एक ऐसे देश के लिए जहां अनौपचारिक श्रम आर्थिक गतिविधि की रीढ़ है, श्रम सुधार को आर्थिक दक्षता के साथ-साथ श्रमिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। सतत श्रम शासन को कमजोर करने की नहीं, बल्कि सहकारी संघवाद, संस्थागत जवाबदेही और सामाजिक न्याय के माध्यम से अधिकारों को मजबूत करने की आवश्यकता है।